>

Title: Need to obtain the views of the local people before setting up any industry in tribal areas of the country.

श्री यशवंत लागुरी : महोदय, मैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित विषय कार्यवाही में शामिल करने की मांग करता हूं। आदिवासी क्षेत्र में जब कोई उद्योग लगता है या खनन के लिए अनुमति की जरूरत होती है, इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है कि स्थानीय लोगों की राय शामिल की जाती है। इसमें व्यवस्था है कि जहां उद्योग लगेंगे, उनमें जो भी गांव आएंगे, वहां के लोगों की ग्राम सभा के माध्यम से राय ली जाएगी। लेकिन यह इस ढंग से कराया जाता है जिससे प्रतीत होता है कि इसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। यह सच है कि उद्योगपति, खनन करने वाले मालिक निश्चत ही आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। आदिवासी लोगों से पूछा जाता है कि इनको उद्योग लगाने दिया जाए या नहीं। इसमें एक डेट फिक्स की जाती है और गांव के लोगों को बुलाया जाता है और सामने पूछकर मत व्यक्त करने की व्यवस्था की जाती है। इसमें जो उद्योगपतियों का विरोध करता है वह प्रक्रिया खत्म होने के बाद उनके रोषका शिकार बनता है।

सभापति महोदय : लागुरी जी, अगर आदिवासी एरिया में इंडस्ट्रलाइजेशन नहीं होगा तो उनको पिछड़ापन दूर कैसे होगा? अगर लोग कहेंगे कि हम नहीं बनाने देंगे तो आउटकम क्या होगा?

श्री यशवंत लागुरी: मैं उद्योग के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं। ग्राम सभा की व्यवस्था में उद्योगपति कुछ वादे करते हैं और प्रक्रिया खत्म होने के बाद उद्योग लग जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई चैकिंग व्यवस्था नहीं है कि जो वादे किए थे उसे कार्यरूप में रुपांतरित किया गया है या नहीं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

सभापति महोदय: मैं सतपाल जी का उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर वे आगे आ जाएं, मैं इसकी अनुमति देता हूं ताकि उन्हें निकलने का मौका न मिले।